



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1980/ज्येष्ठ 15, 1902

No. 152]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1980/JYAISTHA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1980

आधिकार

क्षा० का० नि० 286(अ).—बेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य के सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच नौवहन में सहयोग के लिए, एक करार हुआ है जो इसके साथ संतुलन है;

और उक्त करार के मनुष्ठेव 12 में, व्यतिकारिता के प्रावाहर पर बेकोस्लोवाक जलयानों के द्वारा अर्जित दलाई-भाई से होने वाली आय पर कर के संबंध में बोहेरे करावान से बचने के बारे में उपर्युक्त है;

मत: ध्व, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 90 और कम्पनी (लास) अंतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश करती है कि उक्त करार के उक्त मनुष्ठेव के उपर्युक्त भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अनुबंध

जहाजरानी में सहयोग पर बेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

बेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार ;

दोनों देशों के बीच सन्तुष्टि मन्दवदी तथा जहाजरानी सेवाओं को विकसित एवं सुदृढ़ करने की इच्छा से ;

दोनों देशों के बीच दिनांक 4 विसम्बर, 1974 के आपार तथा प्रशायगी करार का उल्लेख करते हुए ;

प्रार्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए बेकोस्लोवाक-भारतीय समिति की सिफारिशों को व्याप में रखते हुए ;

बेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की भौगोलिक स्थिति को वेष्टते हुए जिसे एक भू-आवद्य देश होने के कारण भ्रष्ट देशों के पतनों का उपयोग करना होता है ; नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

1. समुद्री नीपरिवहन के भोवत्र में दोनों देशों के बीच सड़पोर्ट, प्रभुसत्ता की समानता, राष्ट्रीय हितों तथा पारस्परिक लाभ एवं सहायता के सिद्धांतों पर आधारित होगा।

2. इस करार के उपबन्ध दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच द्विपक्षीय जहाजरानी पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 2

1. इस करार के अनुच्छेद 1 के अनुसार दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हैं कि द्विपक्षीय व्यापार के संबंधन में सहायता देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच माल लाने-जाने के लिए अपने-अपने जहाज देंगे।

2. दोनों पक्ष बेकोस्लोवाकिया द्वारा नामित पत्तनों तथा भारत के पत्तनों के बीच जहाजरानी सेवाओं के विकास में सहयोग देंगे, और जहाजरानी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी अपने संगठनों के बीच पारस्परिक सम्पर्क बढ़ायेंगे।

अनुच्छेद 3

1. संविदाकारी पक्ष के 'जलपोत' शब्द का आशय उस पक्ष के अपने के नीचे समुद्री यात्रा कर रहे किसी भी व्यापारिक जलपोत से अपने दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के अपने-अपने जहाजरानी संगठनों द्वारा, अपने कानूनों के अनुसार, निश्चित समय के लिए किराये पर लिये गये किसी भी व्यापारिक जलपोत से होगा।

2. इस शब्द में दोनों पक्षों के युद्ध-पोत तथा मरम्म-पोत शामिल नहीं होंगे।

3. व्यापारिक जलपोत के 'कर्मविल के सरस्य' शब्दावली का अभिप्राय ऐसे किसी भी व्यक्ति से होगा, जिसे जलपोत की सेवा में समुद्री यात्रा के दौरान जलपोत पर वास्तव में कार्य करने के लिए नियमित किया गया हो और जिसका नाम कर्मविल की सूची में शामिल किया गया हो।

4. अनुच्छेद 2 के अनुसार, बेकोस्लोवाकिया द्वारा नामित पत्तन, व पत्तन होंगे जो बेकोस्लोवाकिया के सम्बन्धित संगठनों द्वारा नामित किये गये हों।

अनुच्छेद 4

1. दोनों संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि बेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की भौगोलिक स्थिति को और बेकोस्लोवाकिया के जहाजी बेहों की क्षमता को, तथा उसकी इस क्षमता के कारण माल को इतर देशों के पोतों द्वारा लाने-जाने की जरूरत को भी, आसतौर पर उन देशों के पोतों द्वारा जिनके समुद्री पत्तनों से होकर माल भेजा जाए और जिनके पोत भारत की जहाज कम्पनियों के सहयोग से अपने पत्तनों तथा भारत के पत्तनों के बीच समुद्री सेवा सम्पर्क रखते हों, यथोचित रूप से व्यापार में रहेंगे।

2. उपर्युक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्ष अपने राष्ट्रीय माल के एक समुद्रित भाग को इतर देशों के जलपोतों के लिए विशेषकर उन देशों के जलपोतों के लिए सुरक्षित रखने पर सहमत होते हैं जिनके पत्तनों से होकर राष्ट्रीय माल को लाया और ले जाया जाता है।

3. संविदाकारी पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि दोनों पक्षों के जहाजरानी संगठनों को, औपर पैरामार्क 2 के मंत्रांत किये गये आरक्षण के अनुरूप, दोनों देशों के बीच भाने-जाने घासे राष्ट्रीय माल को लाने-जाने के कार्य में समान रूप से हिस्सा बनाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 5

1. संविदाकारी पक्ष इस करार के अधीन की जाने वाली गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम बेकोस्लोवाक पक्ष की ओर से

"बेकोफाक्स ग्रान" को और भारतीय पक्ष की ओर से विशिष्ट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लिमिटेड अम्बर्ह को सौंपते हैं।

2. प्रत्येक राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनी, इस सेवा के लिए सौंपे गए जलपोतों का संचालन तथा व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से करेगी और ऐसे कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय परिणामों तथा साथ ही उन देशों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी जो जलपोतों के संचालन से उत्पन्न हो सकते हैं।

3. प्रत्येक पक्ष, यदि आवश्यक हो, तो दूसरे पक्ष को सूचित करके उपर बताए गए संगठनों के स्थान पर किसी अन्य संगठन को नामित कर सकता है।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक पक्ष किसी अन्य देश के साथ अपने व्यापार के मामले में दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के बेड़े के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि दूसरे पक्ष के व्यापारिक बेड़े के विकास तथा उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के भोवत में उस देश की विधि के अनुसार अपनी जहाजरानी कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कार्यालय स्थापित कर सकता है।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी दोनों देशों में से किसी भी देश के जलपोत, जाहे उनमें माल लदा हो अथवा न लदा हो, दूसरे देश के पत्तनों में प्रवेश करने, उहरने और रखाने होने में उन अनुकूलतम सुविधाओं के लाभ के हक्कदार होंगे जो उस देश के कानून, नियम एवं विनियमों के अंतर्गत किसी दौसरे देश के अपने के अधीन जाने वाले जहाजों को प्राप्त होती है। किन्तु यह सिद्धात तटीय नीपरिवहन में रह जहाजों पर लागू नहीं होगा।

2. दोनों पक्ष, अपने पत्तनों में जलपोतों को सहायता प्रदान करने के विशेषकर बंफर्टों, फालतू पुजारी को उपलब्ध करने वालापान प्रादि का प्रबन्ध करने, मरम्मत करने तथा गोदी में जहाज उतारने जलपोत भेजने संबंधी साधारण औपचारिकताओं को पूरा करने तथा कर्मविल के सदस्यों के नाम प्रविष्ट करने के उद्देश्य से प्रभावी उपाय करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 9

एक पक्ष द्वारा जारी किये गये अवधार स्वीकार किये ये जहाज के सभी दस्तावेज, जिनमें राष्ट्रीयता, पंजीकरण, टनभार तथा सर्वेक्षण से सम्बन्धित दस्तावेज भी शामिल हैं, दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

अनुच्छेद 10

यदि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को जलपोत क्षतिग्रस्त हो जाय, उथले समुद्र में फंस जाय, किनारे पर भा जाय अथवा कोई अन्य दुर्घटना हो जाय तो जलपोत, माल, कर्मविल तथा यात्री अथवा पक्ष के राज्य क्षेत्र में वही सहायता प्राप्त होती है जो उसके राष्ट्रीय जलपोतों, माल, कर्मविल तथा यात्रियों को प्राप्त होती है। ऐसा करते समय प्रत्येक पक्ष के अपने-अपने कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखा जायेगा।

अनुच्छेद 11

दोनों देशों के बीच समुद्र-परिवहन से सम्बन्धित सभी प्रदायगियां, दोनों देशों के बीच लागू भवायगी-करार के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

अनुच्छेद 12

चेकोस्लोवाक जलपोतों को माल-भाड़े से जो अःन्वनी होगी उस पर भारतीय प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिकता के आधार पर भारत की ओर से कोई आय-कर न लगाया जाएगा, अथवा न वसूल किया जाएगा ।

अनुच्छेद 13

संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मतभेदों खो बातबीत द्वारा तथा किया जाएगा ।

अनुच्छेद 14

1. दोनों देशों के बीच अहाजरानी सेवाओं के संचालन से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार-विमर्श दोनों देशों के प्राधिकृत संगठनों के बीच होगा, जो इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अवधिक के लिए करार करेंगे ।

2. इस प्रकार के करार विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में होंगे : सेवाओं की भारम्बारता, माल के लादने और उतारने के पत्तनों का नामांकन, भाड़े की दरें और अहाजरानी सेवाओं से सम्बन्धित अन्य ब्यौरे ।

अनुच्छेद 15

वर्तमान करार उन पक्षों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू हो जाएगा, जिनमें इस बात को पुष्ट की गई हो कि इसे दोनों पक्षों की सांविधिक अधिकारियों के अनुसार अनुमोदित कर दिया गया है और यह पांच बर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह करार का सब तक स्वतः हमेशा एक-एक बर्ष के लिए नवीकृत होता रहेगा जब तक कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसकी वैधता की अवधि समाप्त होने से छः महीने पूर्व अन्यथा नोटिस न दे दे ।

नई विली में उन्नीस सौ अठहत्तर के नवम्बर मास के तीसरे विन दर्शकी में दो मूल प्रतियों में निष्पादन किया गया । दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं ।

ह०

(फ्रिजेक मारेस)

चेकोस्लोवाक समाजवादी
गणराज्य की सरकार की ओर से

ह०

(एस० वाई० रानाडे)

भारत सरकार को ओर से

पार्श्व-पत्र

नई विली

3 नवम्बर, 1978

सन्दर्भ : अनुच्छेद-4

महामहिम,

भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच द्वितीय जहाजरानी करार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते समय सारे माल को दोनों देशों के बीच समाता के आधार पर पर बाटे जाने के प्रश्न पर भी सर्वधार्मिक विचार किया गया था । जिस आधार पर यह बंटवारा किया जायेगा उसका उक्त करार के अनुच्छेद 4 में मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है । बंटवारे की अवस्थाओं को अधिक सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाये जायेंगे ।

क. राष्ट्रीय सामान्य माल :

1 उक्त करार के अनुच्छेद 4/2 में, तीसरे देश के भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों के लिए राष्ट्रीय सामान्य माल के आरक्षण के उल्लेख से यह अधिक्रेत होगा कि दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले कुल राष्ट्रीय सामान्य माल का 20 प्रतिशत माल तीसरे देशों के भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों के लिए आरक्षित होगा, विशेषकर उन देशों के पोतों के लिए जिनके पत्तनों से होकर राष्ट्रीय माल आता-जाता हो ।

2. दोनों पक्षों के राष्ट्रीय भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों को जहाँ तक अवधार्य हो, माल उठाने तथा माल-माड़े से होने वाली कमाई,

दोनों के बारे में समता के आधार पर, और इस व्यापार में आम तौर पर दी जाने वाली सेवाओं के अनुरूप राष्ट्रीय सामान्य माल के शेष 80 प्रतिशत माल को ले जाने का अधिकार होगा ।

क. राष्ट्रीय थोक माल :

1. समस्त राष्ट्रीय थोक माल के परिवहन में, दोनों देशों के राष्ट्रीय भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों की, प्रतिस्पद्धार्थक माड़ा वर्तों और शर्तों के प्रश्न समता के आधार पर, भाग लेने का अधिकार होगा ।

2. दोनों पक्षों की ओर से थोक माल के मामले में समन्वयकारी निकाय होंगे : चेकोस्लोवाक पक्ष को ओर से जेवोकाश, प्राहा; और भारतीय पक्ष की तरफ से द्रान्सकार्ट नई विली एवं विविंग कारपोरेशन ग्राफ इंडिया, बम्बई ।

ग. इस करार के सम्पन्न होने के छः महीने के भीतर, इस करार के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सक्षम संगठन कार्यवान त सम्बन्धी पहलुओं को विनियमित करने के लिए आवश्यक वाणिज्यिक अवस्थाएं करेंगे ।

मैं इस पत्र की विषयवस्तु की पुष्टि के लिए आभारी होऊंगा ।

मेरी परम आधार भावना का आवश्यक स्वीकार करें ।

आपका,

(एस० वाई० रानाडे)

सचिव, भारत सरकार

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

महामहिम श्री फ्रिजेक मारेस

प्रथम उप-विदेश-व्यापार मंत्री

चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार

पार्श्व-पत्र

नई विली

3 नवम्बर, 1978

सन्दर्भ : अनुच्छेद-4

महामहिम,

आपका 3 नवम्बर, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है—

“भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच द्वितीय जहाजरानी करार के अधीन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते समय सारे माल को दोनों देशों के बीच समाता के आधार पर बाटे जाने के प्रश्न पर भी सावधानपूर्वक विचार किया गया था । जिस आधार पर यह बंटवारा किया जायेगा उसका उक्त करार के अनुच्छेद 4 में मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है । बंटवारे की अवस्थाओं को अधिक सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाये जायेंगे ।

क. राष्ट्रीय सामान्य माल :

1. उक्त करार के अनुच्छेद 4/2 में, तीसरे देश के भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों के लिए राष्ट्रीय सामान्य माल के आरक्षण के उल्लेख से यह अधिक्रेत होगा कि दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले कुल राष्ट्रीय सामान्य माल का 20 प्रतिशत माल तीसरे देशों के भाष्टे के अधीन चलने वाले पोतों के लिए जिनके पत्तनों से होकर राष्ट्रीय माल आता हो ।

2. दोनों पक्षों के राष्ट्रीय भाष्टों के अधीन चलने वाले पोतों को जहाँ तक अवधार्य हो, माल उठाने तथा माल-माड़े से होने वाली कमाई,

क. राष्ट्रीय थोक माल :

1. समस्त राष्ट्रीय थोक माल के परिवहन में, दोनों देशों के राष्ट्रीय भाष्टों के अधीन चलने वाले पोतों की, प्रतिस्पद्धार्थक माड़ा वर्तों और शर्तों के अधीन समता के आधार पर, भाग लेने का अधिकार होगा ।

2. दोनों पक्षों की ओर से दोनों भाल के मामले में समन्वयकारी निकाय होने : चेकोस्लोवाक पक्ष की ओर से जेनोफोना, प्राहा; और भारतीय पक्ष की तरफ से ट्रान्सजार्ट, नई दिल्ली एवं विशिष्ट कारपोरेशन ग्रॉप इंडिया, बम्बई।

ग. इस करार के सम्बन्ध होने के लिए महीने के भीतर, इस करार के मत्तूंगत विनियोग समझौता, कार्यनालन संबंधी पहलुओं को विनियोग करने के लिए आवश्यक व्याख्याएं करेंगे।

मैं इस पत्र की विषयवस्तु की पुष्टि के लिए आभारी होऊंगा।"

मैं इस बात की पुष्टि करते हुए गौरव का प्रत्युमन कर रहा हूँ कि आपने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है, उसमें हम दोनों के बीच हमासमझौता ठीक-ठीक अभिव्यक्त हो गया है।

मेरी परम प्रादर भावना का आश्वासन स्वीकार करें।

आपका,

(फ्रेजिजेक मोरेस)

प्रथम उप-विदेश व्यापार मंत्री

चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार

महामहिम श्री एस० बाई० रानाडे

सचिव, भारत सरकार

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

[फा० सं० 11(22) 66-वि० कर प्रभाग]

जे० सी० कालरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1980

INCOME-TAX

G.S.R. 286(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India on co-operation in shipping has been concluded;

And whereas Article 12 of the said Agreement provides for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income derived from the freight earnings of Czechoslovak vessels on the basis of reciprocity;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Article of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India on cooperation in shipping.

The Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India;

Desirous of developing and strengthening maritime relations and shipping services between the two countries;

Referring to the Trade and Payments Agreement between both countries dated December 4th, 1974;

Taking into consideration the recommendations of the Czechoslovak-Indian Committee for Economic, Trade and Technical Cooperation;

Taking into account the geographical position of the Czechoslovak Socialist Republic, which being a land-locked country has to make use of the seaports of third countries;

Have agreed as follows :

Article 1

1. In accordance with article 1 of this Agreement, both field of maritime navigation shall be based on the principles of sovereign equality, national interests and mutual advantage and assistance.

2. The provisions of this Agreement shall be applicable to bilateral shipping between the two Contracting Parties.

Article 2

1. In accordance with article 1 of this Agreement, both parties agree to contribute to the participation of their vessels in the carriage of cargo between the two countries in order to assist the promotion of bilateral trade.

2. The Parties will contribute to the development of shipping services between the ports nominated by Czechoslovakia and the ports of India, and develop mutual contacts among their organisations responsible for shipping activities.

Article 3

1. The term "vessel" of the Contracting Party shall mean any merchant vessel sailing under the flag of that Party or time chartered by the respective shipping organisations of either Party, in accordance with its laws.

2. This term would exclude warships and fishing vessels of both the Parties.

3. The term "member of the crew" of a merchant vessel shall mean any person actually employed for duties on board during voyage in the service of a vessel included in the crew list.

4. Ports nominated by Czechoslovakia according to Article 2 are ports nominated by the concerned Czechoslovak organisations.

Article 4

1. The Contracting Parties agreed to take due note of the geographical position of the Czechoslovak Socialist Republic and the capacity of the Czechoslovak fleet, as well as the necessity resulting therefrom to utilize the transport of goods by vessels of third countries, especially those via whose sea-ports the goods are transhipped and whose ships maintain maritime service between their own ports and ports in India in cooperation with Indian liner companies.

2. In recognition of the above mentioned position both Parties agree to reserve a reasonable share of their national cargo to third flag vessels especially those through whose ports national cargoes get transported.

3. The Contracting Parties further agree that the shipping organisations of the two sides have the right to participate equally in the carriage of national cargoes moving between the two countries, consistent with reservation made under para (2) above.

Article 5

1. The Parties entrust Cechofracht Prague on behalf of Czechoslovak side and the Shipping Corporation of India Limited, Bombay on behalf of Indian side with the task to co-ordinate the activities resulting from this Agreement.

2. Each national shipping line shall operate and administer its vessels assigned to this service independently and shall assume full responsibility for financial results of such operations as well as for claims which might arise due to the operation of the vessels.

3. Each Party may, if necessary, nominate any other organisation in place of the above by notifying to the other Party.

Article 6

Each Party will avoid competition with the fleet of the other in its trade with third countries and desist from such

activities as would prejudice the growth and utilisation of the merchant fleet of the other party.

Article 7

Each Party may establish a representation for its shipping companies in the territory of the other party in accordance with the laws of that country.

Article 8

1. Vessels of either country with or without cargoes therein, will, while entering, staying in or leaving the ports of the other country, enjoy the most favoured facilities granted by their laws, rules and regulations to ships under third countries flags. This principle shall not, however, apply to ships engaged in coastal navigations.

2. The Parties shall endeavour to take effective measures aiming at conveyance of assistance to vessels in their ports concerning particularly delivery of bunkers, spare parts, catering, etc. repairs and docking, simple formalities of vessels dispatch, and enrolment of crews.

Article 9

All ship documents including those relating to nationality registration, tonnage and survey issued or recognised by one Party shall be recognised by other Party.

Article 10

If a vessel of one of the Parties suffers shipwreck, runs aground, is cast shore or suffers any other accident, the vessel, the cargo, the crew and the passengers shall receive in the territory of the other Party the same assistance which is accorded to its national vessels, cargo, crew and passengers. This will be subject to the respective laws and the international obligations of each of the Parties.

Article 11

All payments relating to sea transport between the two countries shall be effected in accordance with the provisions of the payments agreement in force between the two countries.

Article 12

No Indian Income Tax shall be levied or collected by Indian Authorities on freight-earnings of Czechoslovak vessels on the basis of reciprocity.

Article 13

All differences between Contracting Parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled by negotiation.

Article 14

1. All matters concerning the operation of shipping services between both countries will be discussed between the authorised organisations of both countries, who for this purpose will conclude agreements for specified periods.

2. Such agreements shall particularly deal with matters such as frequency of services, nomination of loading and discharging ports, freight rates, and other details relating to shipping services.

Article 15

The present Agreement will come into force on the date of the exchange of notes confirming that it has been approved in accordance with the constitutional requirements of both Parties and will remain valid for a period of five years. After the expiry of this period the Agreement will be automatically renewed always for one year unless notified to the country by one of the Parties by giving notice six months prior to the expiry of the period of validity.

Done and signed in New Delhi on the 3rd Day of November one thousand nine hundred and seventy eight in two original copies in English both texts being equally authentic.

Sd/-

(Frantisek Mares)

Sd/-

(S. Y. Ranade)

On behalf of the Government
of the Czechoslovak

On behalf of the
Government of India.

Socialist Republic.

SIDE LETTER

New Delhi, the 3rd November, 1978

Reference Article 4

Excellency,

While discussing various aspects of the bilateral shipping agreement between India and Czechoslovakia the question of sharing all cargo between the two countries on the basis of equality was also carefully considered. Article 4 of the said Agreement broadly states the basis on which this sharing will be effected. The following guidelines will be followed to make the sharing arrangements more precise and specific.

A. National General Cargo :

1. Reference to reservation of national general cargo for third flag vessels article 4/2 of the said Agreement will imply that 20 per cent of all national general cargo moving between the two countries will be reserved for the vessels of third flag countries especially those through whose ports national cargo moves.
2. The national flag vessels of the two Parties will have the right to carry the remaining 80 per cent of the national general cargo on the basis of equality both in respect of lifting and freight earnings as far as practicable and subject to the service usual in this trade being rendered.

B. National Bulk Cargo

1. In the carriage of all national bulk cargo the national flag vessels of the two countries will have the right to participate on the basis of equality subject to competitive freight rates and conditions.
2. The coordinating bodies in the case of bulk cargo on behalf of the Parties will be; Cechofracht, Praha, on Czechoslovak side and Transchart, New Delhi, and the Shipping Corporation of India, Bombay, on Indian side.

C. Within six months of the conclusion of this Agreement the competent organisations specified under this agreement will conclude the necessary commercial arrangements for regulating the operational aspects.

I shall feel grateful for the confirmation of the contents of this letter.

Assuring you of my highest consideration.

Yours sincerely,

Sd/-

S. Y. RANADE, Secy.
to the Government of India,
Ministry of Shipping & Transport

H. E. Mr. Frantisek Mares.

First Deputy Minister of Foreign Trade,
Government of the Czechoslovak Socialist Republic.

SIDE LETTER

New Delhi, the 3rd November, 1978

Reference Article 4

Excellency,

I acknowledge receipt of your letter of 3 November 1978 which reads as follows :

While discussing various aspects of the bilateral shipping agreement between India and Czechoslovakia the question of sharing all cargo between the two countries on the basis of equality was also carefully considered. Article 4 of the said Agreement broadly states the basis on which this sharing will be effected. The following guidelines will be followed to make the sharing arrangements more precise and specific.

A. National General Cargo :

1. Reference to reservation of national general cargo for third flag vessels in article 4/2 of the said Agreement will imply that 20 per cent of all national general cargo moving between the two countries will be reserved for the vessels of third flag countries especially those through whose ports national cargo moves.
2. The national flag vessels of the two Parties will have the right to carry the remaining 80 per cent of the national general cargo on the basis of equality both in respect of lifting and freight earnings as far as practicable and subject to the service usual in this trade being rendered.

B. National Bulk Cargo :

1. In the carriage of all national bulk cargo the national flag vessels of the two countries will have the right

to participate on the basis of equality subject to competitive freight rates and conditions.

2. The coordinating bodies in the case of bulk cargo on behalf of the Parties will be : Cechofracht, Praha, on Czechoslovak side and Transchart, New Delhi, and the Shipping Corporation of India, Bombay, on Indian side.

C. Within six months of the conclusion of this Agreement the competent organisations specified under this agreement will conclude the necessary commercial arrangements for regulating the operational aspects.

I shall feel grateful for the confirmation of the contents of this letter."

I have the honour to confirm that the contents of your letter correctly set out the understanding reached between us.

Assuring you of my highest consideration,

Yours sincerely,

Sd/-

FRANTISEK MARES, First Dy. Minister of Foreign Trade
Government of the Czechoslovak
Socialist Republic

H. E. Mr. S. Y. RANADE, Secy.

H. E. Mr. S. Y. RANADE,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Shipping and Transport.

[F. No. 11(22)66-FID]
J. C. KALRA, Jt. Secy.